(b) since how long these proposals are pending with Government for approval;

(c) how many of these have been approved by Government so far; and

(d) what are the reasons for not approving the proposals specially from Assam and sitting over there for years together?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No Flood Management Scheme prepared by the Government of Assam is pending with the Union Government for approval.

(b) Does not arise.

(c) Twenty-nine Flood Management Schemes costing about Rs. 109 crores have been approved by the Unon Government so far.

(d) Does not arise.

Cadre reviews in CWC

8478. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether cadre reviews are carried out in all the groups in Central Water Commission (CWC);

(b) if so, the reasons for not carrying out the reviews in all the grades in C.W.C.;

(c) how many cadre reviews have been carried out in Central Water Engineering Service in the last fifteen years; group-wise;

(d) whether DPC are required to be held every years as per the existing rules but the same are not being held in CWC; and

(e) if so, the reasons for not conducting yearly DPCs from Extra Assistant Director to Assistant Director in the four years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) During the last 15 years, two cadre reviews have been carried out for the Central Water Engineering (Group 'A') service. Cadre reviews of other services and grades in the Central Water Commission have also been taken up.

(d) and (e) The Departmental Promotion Committees (DPCs) generally meet on annual basis for considering promotions in various grades. However, in certain cases, unavoidable factors like court cases, updating of seniority lists, non-availability of personal records of the officers concerned in time etc., lead to delays in holding DPC meetings.

बिहार की ओर से प्रस्ताव

8479. **श्री आस मोहम्मद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सिंचाई परियोजना की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने हेतु जलाशय का निर्माण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति के लिए दो योजनाएं नामश: कदवान जलाशय परियोजना और कन्हर जलाशय परियोजना प्रस्तुत की है ।

बिहार सरकार ने प्रारंभ में केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए कदवान जलाशय परियाजना पर एक प्रस्ताव अगस्त, 1987

में प्रस्तुत किया था। इस परियोजना में इन्द्रा पुरी बराज पर सोन नहर प्रणाली की जल उपलब्धता के स्थिरीकरण की परिकल्पना की गई है। बाद में, राज्य सरकार ने प्रस्ताव में एक विद्युत घटक भी जोड़ा था। केन्द्रीय जल आयोग में जांच के पश्चात् राज्य सरकार को यह रिपोर्ट इस अनुरोध के साथ वापिस कर दी गई थी कि जलाशय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्रों की जल मग्नता के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों की सहमति सहित एकीकृत संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश सरकार की सहमति अब प्राप्त कर ली गई है। परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी परियोजना को संशोधित करती है तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की उसके क्षेत्र की जलमग्नता के बारे में तथा एकीकृत संशोधित परियोजना रिपोर्ट के बारे में अपेक्षित तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करती है।

184.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कन्हर जलाशय योजना, जिसका कृष्य कमान क्षेत्र 5.90 लाख हेक्टेयर फुट है, केन्द्रीय जल आयोग को 1987 में बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बिहार और मध्य प्रदेश के लिए क्रमश: 4.30 लाख हेक्टेयर फुट एवं 1.60 लाख हेक्टैयर फुट कृष्य कमान क्षेत्र निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार को बिहार सरकार के प्रस्ताव पर अभी सहमति देनी है। परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि बिहार सरकार कितनी जल्दी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करती है तथा केन्द्रीय सरकार से आवश्क तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करती है।

Central Ground Water Board

8480. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Ground Water Board has prepared a centrally sponsored scheme for providing assistance to the States for ground water recharge;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Ground Water Board has formulated a Centrally Sponsored Scheme to assist the State Governments in artificial recharge of ground water. The estimated cost of the scheme is Rs. 81 crores of which Central and State share will be Rs. 42 crores and Rs. 39 crores, respectively

(c) Does not arise.

(d) Scheme is at the consultation stage with the concerned agencies.

World bank aided Subernarekha Multipurpose project

8481. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the news appearing in the Times of India dated 24th April 1995, under the caption "project incomplete after 25 years";

(b) if so, the reaction of the Government thereto; and

(c) what are the reasons that the World Bank aided Subernarekha Multipurpose Projects has failed to make much head-way even after 25 years since its inception?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.